और.... एक शेर

तू भी ऐ शख़्स कहां तक मुझे बर्दाश्त करे
बार-बार एक ही चेहरा नहीं देखा जाता

-अब्बास ताबिश

लोकमत समाचार

तमसो मा ज्योतिर्गमय

शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते है, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से. ■ अज्ञात

संपादकीय

सेवा का अधिकार जनता के हक में अच्छा कदम

महाराष्ट्र की आम जनता को निश्चित समयसीमा में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की गारंटी देनेवाले सेवा का अधिकार विधेयक का विधानसभा में पारित होना निश्चय ही जनता के लिए बड़ी राहत की बात है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह कहना सही है कि इस विधेयक से जनता को अपने काम निश्चित समय पर पूरे कराने की गारंटी मिलेगी. उम्मीद है कि जनता को सरकारी दफ्तरों का बार-बार चक्कर लगाने के लिए मजबूर करने वाले सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों का रवैया इस विधेयक के कानून बनने के बाद बदलेगा, क्योंकि निश्चित समय सीमा के भीतर निर्धारित सेवाओं को उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारियों पर पांच सौ से पांच हजार रु. तक जुर्माना लगाया जाएगा. मुख्यमंत्री का यह कहना उम्मीद बंधाता है कि आरटीआई की तरह यह कानून भी क्रांतिकारी साबित होगा और इसके तहत समय पर सरकारी सेवा उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारी और कर्मचारी की नौकरी भी जा सकती है. सेवा का अधिकार कानून देश के दस राज्यों में पहले से ही लागू है. भाजपा विधायक सुरेश हलवणकर ने बताया कि उन्होंने दसों राज्यों में इस कानून की स्थिति का अध्ययन किया है और मध्य प्रदेश में यह कानून सफल है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में यह कानून लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है. उम्मीद है कि जिन राज्यों में यह कानून सफल नहीं हो पाया है, वहां की असफलता से सबक लेकर सरकार ने आवश्यक प्रावधान इस विधेयक में किया होगा. असल में सिर्फ कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं होता. देश भर में आम तौर पर सरकारी कार्यालय समय पर काम नहीं करने के लिए बदनाम हो चुके हैं. छोटे-छोटे कामों को भी लंबे समय तक लटकाकर रखा जाता है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है. अगर सरकारी अधिकारियों पर निर्धारित समय में काम पूरा करने का दबाव रहे तो भ्रष्टाचार की आशंका कम होती है. मध्य प्रदेश में यह कानून जिन वजहों से सफल है, उन्हें अपनाया जा सकता है. आवश्यकता होने पर जनता को तय समय सीमा में सेवा उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है. सरकार का यह कहना इस कानून के प्रभावी होने के बारे में विश्वास जगाता है कि यह कानून लागू होने के बाद इसमें किसी तरह की त्रुटि नजर आने पर उसे तत्काल प्रभाव से दूर किया जाएगा. कोई भी कानून सर्वांगपूर्ण नहीं होता, समय-समय पर नजर आने वाली त्रुटियों को परिमार्जित करके ही उसे प्रभावी बनाए रखा जा सकता है. सरकार अगर इस कानून में बाद में नजर आने वाली त्रुटियों के प्रति सजग रहेगी तो निश्चित रूप से यह कानून राज्य के नागरिकों के लिए वरदान साबित होगा.■■

मिठाई का डिब्बा

सुनील बाबू के इकलौते बेटे की शादी का रिसेप्शन था. भव्य समारोह आयोजित किया गया था. मेहमान खाने-पीने और नाचने-गाने में मशगूल थे. पर सुनील बाबू हस्बे-मामूल मुख्य द्वार पर डटे हुए थे. कुछ देर पहले आगंतुकों का स्वागत कर रहे थे और अब उन्हीं को विदाई दे रहे थे. उनके करीब ही मिठाइयों के छोटे-बड़े डिब्बों का पहाड़-सा खड़ा था. जैसे ही कोई मेहमान जाने के लिए इजाजत मांगता, सुनील बाबू नौकर की ओर इशारा करते. उनका पुराना खिदमतगार राम बहादुर फौरन एक डिब्बा सुनील बाबू को थमा देता. सुनील बाबू उसे मेहमान को सौंपते हुए उसके आने का धन्यवाद करते और झुक कर प्रणाम करते. ज्यों-ज्यों समय सरकता गया, विदा लेने वाले मेहमानों की लाइन-सी लग गई. इसी लाइन में सबसे अंत में खड़े थे जयप्रकाश. सुनील बाबू के खास परिचितों में रहे हैं जयप्रकाशजी और साथ ही रिश्तेदार भी. उन्होंने भी इजाजत मांगी. नौकर ने जैसे ही मिठाई का एक डिब्बा जयप्रकाशजी को देने के लिए सुनील बाबू के हाथ में थमाया, सुनील बाबू ने डिब्बे को वापस नौकर को देते हुए अत्यंत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि लोगों की हैसियत तो देख लिया कर. और एक छोटा सा डिब्बा उठाकर जयप्रकाशजी को थमाते हुए आने के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि भाभीजी व बच्चों को भी साथ लाते तो मुझे कितना अच्छा लगता! जयप्रकाशजी को बाद में कही गई बात तो नहीं सुनाई पड़ी लेकिन जो बात वो सुन चुके थे वो सब सुनने के बाद भी उन्होंने ऐसा प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो. लेकिन पकड़ा हुआ मिठाई का डिब्बा उन्हें इतना भारी लग रहा था कि उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था. घर पहुंचने तक सारे रास्ते जयप्रकाशजी डिब्बे के भार और आकार में संतुलन बिठाने का प्रयास करते रहे. ■■

लघुकथा

सीताराम गुप्ता

महामहिम के पद पर दाग

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

महामहिम, लाट साहब, हिज एक्सीलेंसी के रूप में सम्मान, शान-शौकत, राज-भवन, राष्ट्रगीत की धुन, बिगुल और बंदूक की सलामी. इससे भी बड़ी संवैधानिक ताकत- मंत्री ही नहीं मुख्यमंत्री को भी बर्खास्त करने का अधिकार. संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की अनुकंपा पर निर्भर है. यह बात जरूर है कि राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना होता है तथा राज्यों में मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के निर्णयों का अनुमोदन विधानसभा के बाद राज्यपाल औपचारिक रूप से करते हैं. लेकिन राज्यपाल के पद को मिले संवैधानिक संरक्षण की आड़ में गंभीर अपराध और भ्रष्टाचार करने की छूट कैसे मिल सकती है? पिछले 60 वर्षों के दौरान राज्यपालों के निर्णयों पर विवाद हुए हैं और आरोप भी लगे हैं. उन्हें समय-समय पर हटाया भी गया है. लेकिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव पर दो वर्षों से गंभीर आरोपों की पुष्टि, पुलिस की प्राथमिकी के बाद अदालत में दाखिल चार्जशीट में दस नंबरी आरोपी होने पर भी केंद्र सरकार का अभयदान - संपूर्ण व्यवस्था के लिए कलंक है. इस देश के सबसे बड़े और शर्मनाक - व्यापमं घोटाले में राम नरेश यादव पर राज्यपाल के पद पर रहते हुए सत्ता के दुरुपयोग और रिश्वत लेने के गंभीर आरोप कम्प्यूटर की फाइलों में दर्ज हैं. यादव के पुत्र पर भी गंभीर आरोप थे और संदिग्ध अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई. नियुक्तियों में करोड़ों रुपया कमाने के आरोपी भाजपा के मंत्री, उनके रिश्तेदार, सचिव-सहायक, अधिकारी के साथ राम नरेश यादव का नाम आया. वहीं म.प्र. की सरकार ने अपने पाप छिपाने के लिए

> व्यापमं घोटाले में राम नरेश यादव पर राज्यपाल के पद पर रहते हुए सत्ता के दुरुपयोग और रिश्वत लेने के गंभीर आरोप कम्प्यूटर की फाइलों में दर्ज हैं.

महामहिम राज्यपाल के सिंहासन-संवैधानिक संरक्षण की आड़ ले ली. पुलिस जांच दल के सामने लोहे की दीवार खड़ी करके कहा गया कि अदालत से अनुमति के बाद ही राम नरेश यादव को कठघरे में खड़ा किया जा सकता है. मजेदार बात यह है कि पूर्ववर्ती केंद्र सरकारों की तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई राज्यपालों को हटाया, लेकिन भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की 'शेरवानी' पहने म.प्र. के राज्यपाल पर कृपा बनाए रखी. जहां अन्य राज्यपालों को हटाने के लिए गृह सचिव के फोन से ही काम चलाया गया, वहां 'महामहिम' राम नरेश जी पर नरेंद्र-राजनाथ की कोप दृष्टि क्यों नहीं हो सकी?

व्यापमं घोटाले में 50 से ज्यादा व्यक्तियों की रहस्यमय मौत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने से संभवतः जल्द ही राम नरेश यादव को हटा दिया जाए, लेकिन इस विलंब और व्यवस्था पर विचार की जरूरत है.

कई राज्यपालों ने अपने पद का दुरुपयोग किया. राज्यपालों के पास सामान्यतः विश्वविद्यालयों के कुलाधिकारियों का पद भी होता है. इसलिए कुलपतियों की नियुक्तियों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है. ईमानदार तथा योग्य पृष्ठभूमि वाले राज्यपाल सही व्यक्ति को कुलपति के रूप में चुनते हैं. लेकिन भ्रष्ट कुलपति नियुक्त करने पर वे संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट बनाकर कलंकित कर सकते हैं. कुछ राज्यपालों और राज्य सरकारों ने रिटायर्ड आई.ए.एस. अथवा आई.पी.एस. को कुलपति पद दिए. संभव है कि उनकी प्रशासनिक क्षमता रही हो, लेकिन शैक्षणिक मानदंडों, विश्वविद्यालयों तथा छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान न होने से उन्होंने शिक्षा संस्थानों को बर्बाद किया.

महान संविधान निर्माताओं ने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की होगी. सत्ता की निरंकुशता रोकने के लिए उन्होंने विभिन्न स्तरों पर चेक-बैलेंस की व्यवस्था की. सब एक दूसरे पर निर्भर रहें, लेकिन समाज और राष्ट्र के हित में लोकतांत्रिक असहमतियों का सम्मान करें. निश्चित रूप से पीढ़ियों और समय के साथ सामाजिक राजनीतिक लोग बदले हैं. संविधान समीक्षा आयोग भी बना. लेकिन संविधान में संशोधनों के लिए भी संसद में भारी बहुमत की जरूरत होती है. इसी तरह संविधान की मर्यादाओं और नैतिक मानदंडों की लक्ष्मण रेखा का दायित्व संबंधित व्यक्तियों पर अधिक रहता है. फिर भी सत्ता के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए राज्यपाल अथवा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठने वालों के लिए नई आचार-संहिता पर संसद में सर्वानुमति क्यों नहीं बन सकती? जब आप यूरोप, चीन, अमेरिका के साथ भारत की तुलना करने लगते हैं तो कृपया विचार करें कि किस देश में राज्यपालों और मंत्रियों के पास इतने विशाल राज-भवन, बंगले तथा अनावश्यक ताम-झाम होते हैं. जिन राजधानियों में गरीबों के लिए अच्छे अस्पताल नहीं हैं, वहां कई एकड़ में फैले राजभवनों को अस्पतालों के रूप में क्यों नहीं बदला जा सकता है?■■

'धृतराष्ट्र' न बने बीसीसीआई

राम ठाकुर
खेल पत्रकार
लोकमत समाचार

आखिरकार भारतीय क्रिकेट की छवि को साफ करने की दिशा में प्रयास शुरू हो चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय समिति ने इस दिशा में ऐतिहासिक पहल की है. समिति ने आईपीएल के माध्यम से क्रिकेट से जुड़े ताकतवर पदाधिकारियों, फ्रेंचाइजी मालिकों और जाने-अनजाने में पैसे की लालच में अपना हुनर बेच रहे खिलाड़ियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की है. चूंकि यह शुरुआत है, लिहाजा समिति ने खेल की गरिमा को बनाए रखते हुए कुछ ही चुनिंदा लोगों (गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा) को सजा सुनाई है. लेकिन, इसका यह मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित समिति ने बड़ी मछलियों को नजरअंदाज किया है. समय रहते स्थितियां नहीं सुधरती हैं तो 'भारतीयों का धर्म' माने जा रहे इस खेल की छवि को धूमिल करने वालों की खैर नहीं होगी.

अब तो जागे बीसीसीआई

असल मुद्दा तो देश में क्रिकेट को संचालित कर रहे बीसीसीआई पदाधिकारियों की नीयत का है. बीसीसीआई महज 31 लोगों का सबसे अमीर खेल संगठन है. इसके कायदे-कानून देश के संविधान से भी बाहर हैं. जब कभी भी केंद्र सरकार बीसीसीआई को अपने दायरे में लेने की कोशिश करती है तो उसके ताकतवर 'संचालक' अपने रुतबे का इस्तेमाल कर मामले को रफा-दफा कर देते हैं. दरअसल आईपीएल में धन की बढ़ती बाढ़ से उसके कर्ताधर्ता 'धृतराष्ट्र' बन गए. 'ललित मोदी' ऐसी ही व्यवस्था का नतीजा है. आज जिसे (ललित मोदी) पूरा देश भगोड़ा करार दे चुका है, वह किसी समय बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष के सबसे चहेते थे. आज भी यह महाशय ललित मोदी का समर्थन कर रहे हैं. बीसीसीआई के ढुलमुल बर्ताव के कारण ही एन. श्रीनिवासन आईपीएल में टीम मालिक बन गए. श्रीनि ने बाकायदा बोर्ड के संविधान में संशोधन कर सर्वसम्मति से अपनी टीम को इस धन कमाने वाली स्पर्धा का हिस्सा बना लिया.

श्रीनिवासन की मुंहजोरी

मंगलवार को लोढ़ा समिति द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद आईसीसी चेयरमैन श्रीनिवासन को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए था. उनकी टीम 'चेन्नई सुपर किंग्स' पर दो साल का निलंबन तथा दामाद गुरुनाथ मयप्पन पर लाइफ बैन के बाद श्रीनिवासन को कुछ तो नैतिकता दिखानी चाहिए थी, पर नैतिकता को दरकिनार कर इस महाशय ने डंके की चोट पर इस्तीफा नहीं देने का ऐलान कर दिया. हो सकता है कि अब बीसीसीआई आगामी सितंबर की वार्षिक आमसभा में उनका कार्यकाल खत्म कर दे.

> आईपीएल में धन की बढ़ती बाढ़ से उसके कर्ताधर्ता 'धृतराष्ट्र' बन गए. 'ललित मोदी' ऐसी ही व्यवस्था का नतीजा है.

आईपीएल का भविष्य

आज भले ही कुछ लोग दूधिया रोशनी में चीयरलीडर्स की थिरकन और मसाला क्रिकेट की पहचान बन चुके आईपीएल को बंद करने की मांग कर रहे हों लेकिन यह आसान नहीं है. हालांकि सब जानते हैं कि आईपीएल से कथित तौर पर काले धन के इस्तेमाल की आशंका बढ़ी है. छठे संस्करण में स्पॉट फिक्सिंग जैसे मामलों ने देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है. लेकिन, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि देश में क्रिकेट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. टी-20 की तर्ज पर खेले जा रहे इस खेल ने गांव-कस्बे से जुड़ी होनहार प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय पर एक पहचान दी है. राष्ट्रीय घरेलू क्रिकेट के ढांचे की तुलना में क्रिकेट का यह प्रारूप देश के अनेक होनहार नौजवानों के लिए रोजगार का माध्यम बन चुका है और अंत में फैसला तो देश के नागरिकों को करना होता है जो इस खेल में रच-बस चुके हैं. ■■

सुधार की अच्छी पहल

नजरिया उर्दू प्रेस का

■ राजश्री यादव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की हालिया मुलाकात को भारत-पाक दोनों देशों के उर्दू मीडिया ने तनावभरे संबंधों में सुधार के लिए एक अच्छी पहल बताया है.

श्रीनगर से प्रकाशित **'डेली रोशनी'** ने लिखा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच जो तनाव भरे संबंध थे,

> नीयत में खोट न हो अपनापन हो तो किसी भी तरह की दुश्मनी के दोस्ती में बदलने में देर नहीं लगती.

उम्मीद है कि रूस के शहर उफा में दोनों के बीच हुई मुलाकात से इस कड़वाहट को कम करने में मदद मिलेगी. वैसे भी नीयत में खोट न हो, अपनापन हो तो किसी भी तरह की दुश्मनी के दोस्ती में बदलने में देर नहीं लगती.

पाकिस्तान के कराची, रावलपिंडी और लाहौर शहरों से प्रकाशित उर्दू डेली **'जंग'** ने लिखा है रूस के शहर उफा में भारत-पाक के प्रधानमंत्रियों के बीच तकरीबन एक घंटे तक चली बातचीत को इस लिहाज से बेहतर करार दिया जा सकता है कि दोनों देशों में समझौतों के जरिए जम्मू-कश्मीर सहित तमाम आपसी विवादों का हल निकालने का बंद दरवाजा एक बार फिर खोलने पर इत्तेफाक ए-राय हो गया है.

पाकिस्तान के कराची से ही प्रकाशित डेली **'उम्मत'** ने लिखा है, भारत-पाक के अब तक के उतार-चढ़ाव भरे रिश्तों को देखते हुए नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की हालिया मुलाकात से सकारात्मक नतीजों की उम्मीदें जोड़ लेना जल्दबाजी होगी. सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और भारत के बीच बेहतर संबंधों की राह में सबसे बड़ा मसला कश्मीर है. भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की छवि एक कट्टर हिंदू रहनुमा और पाकिस्तान विरोधी की रही है.

'इन्कलाब डेली' दिल्ली संस्करण ने बिहार में हाल ही में संपन्न विधानपरिषद चुनावों में भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा है बिहार के विधानपरिषद चुनाव में एनडीए बढ़त मिल जाने पर मीडिया का ये रद्देअमल गुमराह करने वाले प्रोपगेंडा के अलावा और कुछ नहीं है कि ये मिनी विधानसभा चुनाव था, सेमीफाइनल था और इससे भाजपा के हौसले बुलंद हुए हैं. चूंकि इस चुनाव में जनता वोट नहीं करती बल्कि वोटिंग जनता के प्रतिनिधियों के जरिए होती है, इसलिए इसे जनता के एहसासों व जज्बात का आईना नहीं कहा जा सकता. इससे भाजपा के हौसले भले ही बुलंद हुए हों या भाजपा ऐसा जताने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जहां तक मीडिया का सवाल है इसका मकसद जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन का हौसला तोड़ना मालूम होता है.

अखबार ने लिखा है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने इस चुनाव में कम सीटें मिलने पर किसी रद्देअमल का इजहार नहीं किया और ये अच्छा ही किया. उन्हें भाजपा से लोहा लेने की अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए.

और अंत में...

सूरज की किरणें, तारों की बहार
चांद की चांदनी, अपनों का प्यार
हर घड़ी हो खुशियां
इसी तरह मुबारक हो ईद का त्यौहार. ■■

नजर के पार

हादसों में बदलते धार्मिक मेले

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

देश के धर्म स्थलों पर लगने वाले मेले अचानक टूट पड़ने वाली भगदड़ से बड़े हादसों का शिकार हो रहे हैं. नतीजतन श्रद्धालु पुण्य लाभ कमाने के फेर में आकस्मिक मौतों की गिरफ्त में आ रहे हैं. इस क्रम में नया हादसा आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में पुष्करालू उत्सव में स्नान के दौरान घटा. गोदावरी नदी के पुष्कर घाट पर यह उत्सव बारह दिन तक चलता है. लेकिन प्रत्येक 144 साल बाद महा पुष्करालू उत्सव आयोजित होता है, जिसे दक्षिण का कुंभ कहा जाता है. जाहिर है, इस उत्सव में लाखों श्रद्धालु भागीदारी करते हैं. यह घटना इसलिए घटी, क्योंकि करीब आधे घंटे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने तट पर स्नान किया था. उनकी सुरक्षा के लिए सामान्य जन को रोक दिया गया था. लिहाजा भीड़ इकट्ठी हो गई. और जब दोनों मुख्यमंत्री स्नान के बाद लौट गए तो भीड़ को एक साथ घाट पर जाने के लिए छोड़ दिया गया. स्नान करने की जल्दी में कुछ महिलाओं के सीढ़ियों से पैर फिसल गए, नतीजतन भगदड़ मच गई जिसमें 13 महिलाओं समेत 29 लोगों की मौत हो गई.

हमारे देश में धर्म-लाभ कमाने की प्रकृति से जुड़े हादसे अब हर साल देखने में आ रहे हैं. भारत में पिछले डेढ़ दशक के दौरान मंदिरों और अन्य धार्मिक आयोजनों में उम्मीद से कई गुना ज्यादा भीड़ उमड़ रही है जिसके चलते दर्शनलाभ की जल्दबाजी व कुप्रबंधन से उपजने वाली भगदड़ों का सिलसिला जारी है. धर्म स्थल हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम शालीनता और आत्मानुशासन का परिचय दें. किंतु इस

बात की परवाह आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं होती. इसलिए उनकी जो सजगता घटना के पूर्व सामने आनी चाहिए, वह अक्सर देखने में नहीं आती.

हमारे धार्मिक-आध्यात्मिक आयोजन विराट रूप लेते जा रहे हैं. कुंभ मेलों में तो विशेष पर्वों के अवसर पर एक साथ लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों तक लोग एक निश्चित समय के बीच स्नान करते हैं. किंतु, इस अनुपात में यातायात और सुरक्षा के इंतजाम देखने में नहीं आते जबकि शासन-प्रशासन के पास पिछले पर्वों के आंकड़े होते हैं. इसके बावजूद लपरवाही बरतना हैरान करने वाली बात है. दरअसल, कुंभ या अन्य मेलों में जितनी भीड़ पहुंचती है और उसके प्रबंधन के लिए जिस प्रबंध कौशल की जरूरत होती है, उसकी दूसरे देशों के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते. इसलिए हमारे यहां लगने वाले मेलों के प्रबंधन की सीख हम विदेशी साहित्य और प्रशिक्षण से नहीं ले सकते. इसके बावजूद हमारे नौकरशाह भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण लेने खासतौर से यूरोपीय देशों में जाते हैं. प्रबंधन के ऐसे प्रशिक्षण विदेशी सैर-सपाटे के बहाने हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता. ऐसे प्रबंधनों के पाठ हमें खुद अपने देशज ज्ञान और अनुभव से लिखने होंगे.

प्रशासन के साथ हमारे राजनेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और आला अधिकारी भी धार्मिक लाभ लेने की होड़ में व्यवस्था को भंग करने का काम करते हैं. हादसों का दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला फिलहाल टूटता दिखाई नहीं देता. ■■

तोल बोल

आप यह सोचते होंगे कि मुख्यमंत्री होकर पार्टी के लिए पैसा मांग रहा हूं. हम गलत ढंग से पैसे ले सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करते. इसीलिए चंदा मांगना पड़ रहा है.

■ अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

कांग्रेस पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश को बदनाम करने का 'महापाप' कर रही है. वह हताशा के दौर से गुजर रही है.

■ नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री

gñWmnH¦ gmXH¦ : ñd. OdñaÞmÞ XS॥
M`à Z, E[SQ¦fà`b ~¦S : {dO~ XS॥
E[SQa-BZ-Mr\¦ : aïOÐ XS॥
gmXH : {dH¦ñg {_l ★
★ nr. Aïa. ~r. HÞZZ H¦ AZgïa gmU gmXH¦` Xf{` Ed H¦ {bE {Oà_Xïa.

© लोकमत समाचार _ àHÞ{eV g^r gr_Jr H¦ gdñ{Y¦ñïa bñH¦_V _r{S`ï àñ`dÒ {b. H¦ mg ga{j V h.
bñH¦_V _r{S`ï àñ`dÒ {b. H¦ {bE _DH¦ Ed àH¦eH¦ बालाजी मुले Ûïar bñH¦_V _r{S`ï àñ. {b., {Ibñ{Q H¦. 192, 207, 208 E _. AïB. Sr. gr. B¦S{fÒ`b E[à`ï, ~Qr~¦ar, ZxJna _ {DV Ed bñH¦_V ^dZ n. OdñaÞmÞ ZñH¦ _ïJ, ZxJna _ àHÞ{eV.

P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XaÛd{Z : 0712-2423527 (7 bñB¦g) \\Sg : 6618555
Email : gmXH¦` : lsedit.ngp@lokmat.com
{dkmZ : advt.ngp@lokmat.com {dVaÛ : circ.ngp@lokmat.com

इतिहास पर नजर 16 जुलाई

आज के दिन 1969 में पहली बार इंसान को चांद पर पहुंचाने की कोशिश की गई थी. अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के कैप कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ. यान को ले जाने वाले रॉकेट को देखने के लिए पूरे राज्य से दस लाख लोग इकट्ठा हुए थे. रॉकेट छोड़े जाने से पांच सेकेंड पहले इंजिन चालू किया गया और ठीक वक्त पर एक तेज धमाके के साथ अपोलो 11 आकाश की ओर रवाना हो गया. सिर्फ बारह मिनट के भीतर अपोलो 11 पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटने लगा. उसमें सवार थे नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिन्स और एडविन एल्ड्रिन. 21 जुलाई, 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने. ■■

- 1856-हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली.
- 1920-चीन लीग ऑफ नेशन में शामिल हुआ.
- 1979-इराकी राष्ट्रपति अहमद हसन अल बक्र के इस्तीफे के बाद सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति बने.

1990-फिलीपींस में 7.7 तीव्रता के भूकंप से 400 लोगों की मौत.

- 1990-यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा की.
- 2013-बिहार के छपरा जिले के एक स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना के तहत दिए जाने वाले खाने के विषैला होने से 27 बच्चों की मौत और 25 बच्चे बीमार.

पाठकों के पत्र

धार्मिक कट्टरता से बचना होगा

यह माना कि हमारे देश के अधिकांश लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं. इसका मतलब यह कदापि नहीं होता कि हम धर्म की कट्टरता के आगे अपनी जान ही होम कर दें. बाबासाहब आंबेडकर ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 'मनुष्य के लिए धर्म है न कि धर्म के लिए मनुष्य' तात्पर्य यह कि यदि मनुष्य ही नहीं रहेगा तो ऐसा धर्म किस काम का. वर्तमान में मनुष्य धर्म के नाम पर मरने मारने पर उतारू हो जाता है. पिछले वर्ष तीर्थयात्राओं पर काफी लोग दर्शनार्थ गए लेकिन अचानक बाढ़ आने से सैकड़ों लोग जमींदोज हो गए थे जिनका एक वर्ष के बाद भी कोई पता नहीं चल सका है. अब इस वर्ष भी लोग तीर्थयात्राओं में जा रहे है तथा वर्षा के कारण इस वर्ष भी काफी लोग बाढ़ में फंसे. तात्पर्य यह है कि लोग जानबूझकर ऐसा कार्य क्यों करते हैं. धार्मिक यात्राओं के समय सावधानी बरतनी चाहिए. जीवन का विशेष महत्व है जो कभी भी लौटकर नहीं आता है.

■ बी. सी. उके, किरनी

अपना-अपना नजरिया

एक सुनसान रास्ते में घूमते समय नसरुद्दीन ने घोड़े पर सवार कुछ लोगों को अपनी ओर आते देखा. मुल्ला का दिमाग चलने लगा. उसने खुद को लुटेरों के कब्जे में महसूस किया जो उसकी जान लेने वाले थे.

उसके मन में खुद को बचाने की हलचल मची और वह सरपट भागते हुए सड़क से नीचे उतरकर दीवार फांदकर कब्रिस्तान में घुस गया और एक खुली हुई कब्र में लेट गया.

घुड़सवारों ने उसे भागकर ऐसा करते देख लिया. कौतूहलवश वे उसके पीछे लग लिए. असल में घुड़सवार लोग तो साधारण व्यापारी थे. उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को लाश की तरह कब्र में लेटे देखा.

''तुम कब्र में क्यों लेटे हो? हमने तुम्हें भागते देखा. क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? तुम यहां क्या कर रहे हो?'' व्यापारियों ने पास आकर मुल्ला से पूछा.

''तुम लोग सवाल पूछ रहे हो लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर सवाल का सीधा जवाब हो'' मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा. वह अब तक सब कुछ समझ चुका था. व्यापारियों को हैरान देखकर उसने कहा, ''दरअसल सब कुछ देखने के नजरिए पर निर्भर करता है. मैं यहां तुम लोगों के कारण हूं, और तुम लोग यहां मेरे कारण हो.'' ■■
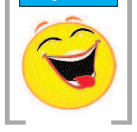
हास्य